



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 725 राँची, शुक्रवार,

27 जुलाई, 2018 (ई०)

### राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

27 जुलाई, 2018

संख्या- 1/नि०वि० विविध 02/16-506/नि.,-- निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 69 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा, 69 (2) के अधीन निबंधन महानिरीक्षक राज्य सरकार के अनुमोदन से निबंधन (दस्तावेजों के निबंधन में पहचान का सत्यापन) नियमावली, 2016 में संशोधन कर निम्नांकित रूप से कंडिका 4(क), (ख), (ग), (घ), (ङ) जोड़ते हैं ।

4 (क) अचल संपत्ति के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज के निबंधन तथा विवाह निबंधन में ऐसे अप्रवासी भारतीय (Non Resident Indian), विदेश में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों (Person of India Origin), पार समुद्री भारतीय नागरिक (Overseas Citizenship of India), विदेशी नागरिकों आदि जिन्हें आधार संख्या प्राप्त नहीं है, हेतु दस्तावेज में आधार संख्या का वर्णन करना तथा आधार का सत्यापन कराना अनिवार्य नहीं होगा ।

4 (ख) ऐसे पक्षकार आधार संख्या के स्थान पर अपना पासपोर्ट संख्या, OCI Card संख्या अथवा संबंधित देश द्वारा निर्गत पहचान संख्या का वर्णन दस्तावेज में करेंगे ।

4 (ग) संबंधित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति दस्तावेज के साथ संलग्न करेंगे जिसे निबंधन कार्यालय में स्केन कर मूल दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाएगा ।

4 (घ) ऐसी स्थिति में जबकि पक्षकार के पास आधार संख्या है, किन्तु किसी रोग के कारण अथवा वयोवृद्ध होने के कारण उसके अंगुलियों के निशान या आँखों की पुतलियों का सत्यापन eKYC के माध्यम से नहीं हो रहा है तो उसके आधार संख्या का सत्यापन उसके आधार रजिस्टर्ड मोबाईल पर OTP द्वारा किया जाएगा ।

4 (ड) OTP के द्वारा आधार सत्यापन के पश्चात e-KYC Data स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा जिसे प्रिंट कर मूल दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाएगा तथा स्कैन कर अपलोड भी किया जाएगा ।

भविष्य में UIDAI के द्वारा विकसित आधार सत्यापन के अन्य प्रकार यथा-Face Recognition आदि के द्वारा भी आधार सत्यापन किया जा सकेगा ।

निबंधन (दस्तावेजों के निबंधन में पहचान का सत्यापन) नियमावली, 2016 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे ।

**नोट:-** निबंधन हेतु प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज तथा प्री-रजिस्ट्रेशन में आधार संख्या का वर्णन वांछनीय होगा जिससे e-KYC के माध्यम से आधार का सत्यापन हो सके ।

यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा ।

दिनांक 24 जुलाई, 2018 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-02 के रूप में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**कमल किशोर सोन,**  
सरकार के सचिव  
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,  
झारखण्ड, रांची ।

-----